RAJYA SABHA

Tuesday, the 23rd February, 1999/
4th Phalguna, 1920 (Saka)

The House met at Eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

RE. IMPOSITION OF PRESIDENT'S RULE IN BIHAR

श्री नरेश यादव (बिहार): महोदय.....(व्यवधान)

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): केन्द्रीय सरकार ने बिहार में लोकतंत्र की हत्या की है। .....(व्यवधान)

श्री नरेश यादव: लोकतंत्र की हत्या की गई है। .....(व्यवधान)... लोकतंत्र की हत्या की गई है और रणवीर सेना .....(व्यवधान)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, it is a murder of democracy. ...*(interruptions)*.....

श्री रामदेव भंडारी: भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी ने रणवीर .....(व्यवधान) सेना से हत्या कराई है। यह इन्हीं दलों की साजिश है। इन्होंने साजिश कर बिहार सरकार को बर्खास्त किया है।.....(व्यवधान)

श्री सरोज दुबे (बिहार): महोदय .....(व्यवधान) बिहार सरकार को बर्खास्त कराया गया है।.....(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, it is the same set of political leaders who have ...*(interruptions)*.....

MR. CHAIRMAN: Don't come to the well. ...*(interruptions)*.....

यहां नहीं, यहां से नहीं।.....(व्यवधान)

श्री रामदेव भंडारी: लोकतंत्र की हत्या हुई। .....(व्यवधान)

श्री नरेश यादव: लोकतंत्र की हत्या हुई। .....(व्यवधान)

श्री सभापति: यहां नहीं .....(व्यवधान) वहां रहिए।. ....(व्यवधान)

श्री रामदेव भंडारी: हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।.....(व्यवधान) इन्हें एक मिनट भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।.....(व्यवधान)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, who is taking the responsibility for the murders taking place after the imposition of President's rule? ...*(interruptions)*..... Mr. Chairman, Sir, who is taking the responsibility for the murders taking place after the imposition of President's rule? ...*(interruptions)*.....

श्री सरोज दुबे: महिलाओं की वकालत करने वाले, एक महिला की चुनी सरकार को हटाते हो। .....(व्यवधान)...

श्री नरेश यादव: आप संविधान के रक्षक हैं। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है, भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। इसे बरखास्त कराइए।.....(व्यवधान)

.....(व्यवधान).....

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो।..... (व्यवधान).... दलितों की हत्या बंद करो।.....(व्यवधान)....

.....(व्यवधान)....

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): It is not proper to raise a point like this. *(interruptions)*. You just raise your point along with arguments. Otherwise, what is the point? ...*(interruptions)*.....

श्री नागमणि (बिहार): इन्होंने चुनी हुई सरकार बरखास्त करने का काम किया है, जानबूझकर दलितों की हत्या कराकर। ये संविधान की हत्यारे लोग है, इसलिए इन्हें बरखास्त कीजिए।.....(व्यवधान)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He is talking about democracy. *(interruptions)*. The democratic process has been murdered. *(interruptions)*. The Delhi *durbar* is worse than the British regime. *(interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, ...*(interruptions)*....

श्री नरेश यादव: बिहार में चुनी हुई सरकार की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या है, सर।.....(व्यवधान)...

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

गैर-सरकारी क्षेत्र में संचार क्षेत्र के लिए पैकेज

*1. श्री गोपाल सिंह चौ० सोलंकी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में संचार क्षेत्र के

लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त पैकेज की घोषणा कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पैकेज के फलस्वरूप संचार सेवा की स्थिति में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा नई दूरसंचार नीति पर सिफारिशें देने के लिए एक दूरसंचार दल का गठन किया गया है। यह दल अन्य बातों के साथ-साथ संचार के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर द्वारा अदा की जा सकने वाली भूमिका पर विचार कर रहा है। मार्च, 1999 के अंत तक इस दल की सिफारिशें प्राप्त हो जाने की संभावना है। दल की सिफारिशें मिल जाने के बाद सरकार अपना दृष्टिकोण तय करेगी।

Development of Tourism in Tamil Nadu

*2. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the number of proposals received from the State Government of Tamil Nadu for development of tourism in the State;

(b) the number of proposals cleared till 31st December, 1998; and the details thereof; and

(c) the number of proposals pending and the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF TOURISM (SHRI ANANTH KUMAR): (a) to (c) Ministry of Tourism in consultation with State Government have prioritised 20 projects for Central Financial Assistance during the year 1998-99 for Rs. 435.00 lakhs. Proposals for 13 projects were received from the State Government. However, on scrutiny of the proposals it was found that the proposals were incomplete as per the Guidelines laid down by the Ministry of Tourism. Therefore, no projects were sanctioned till 31.12.1998. Subsequently however, seven projects amounting to Rs. 87.81 lakhs were sanctioned.

जाली बीमा कारोबार

*3. श्री ईश दत्त यादव:
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में चालू जाली बीमा कारोबार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जाली बीमा कारोबार जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों, एजेंटों और निगम के कार्यालयों की मिलीभगत से चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम को भारी चाट हो रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जीवन बीमा निगम के कार्यकरण को सरल एवं कारगर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय (वैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) पिछले कई वर्षों में सरकार के नोटिस में जीवन बीमा निगम में जाली बीमा कारोबार के मामले आये हैं।

(ग) और (घ) हां। पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	संख्या
1995-96	8
1996-97	3
1997-98	शून्य
1998-99	शून्य

(ङ) सरकार ने इन अनाचारों की जांच करने हेतु केन्द्र सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य सचिव श्री ए. वी. गणेशन की अध्यक्षता में एक उच्च सक्षित प्राप्त समिति नियुक्त की थी। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है जिससे अनाचारों को नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

National Judicial Commission

*4. SHRI PRAFULL GORADIA:

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that eminent jurists, former police officials and